5-5-12

दृष्टि The Vision

सामान्य अध्ययन (टेस्ट - V)

GENERAL STUDIES (Test - V)

मॉड्यूल - V / Module - V

DTVF/17–M–GS5

निर्धारित समय: तीन घंटे *Time allowed: Three Hours*	अधिकतम अंक: 250 *Maximum Marks: 250*

नाम (Name): अनिरुद्ध कुमार

क्या आप इस बार मुख्य परीक्षा में रहे हैं? हाँ ✓ नहीं

मोबाइल नं. (Mobile No.):

ई-मेल पता (E-mail address):

टेस्ट नं. एवं दिनांक (Test No. & Date): V, 07-09-17

रोल नं. [यू.पी.एस.सी. (प्रा.) परीक्षा-2017] [Roll No. UPSC (Pre) Exam-2017]:

0	0	9	8	5	1	4

परीक्षा का माध्यम (Medium of Exam.): हिन्दी

विद्यार्थी के हस्ताक्षर (Student's Signature):

नोट: प्रश्न-पत्र के लिये विशिष्ट अनुदेश अंतिम पृष्ठ पर संलग्न है।

Evaluation Analysis

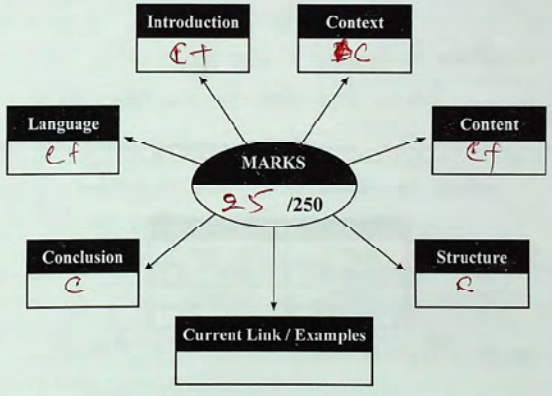

Copyright – Drishti The Vision Foundation

व्यापक विश्लेषण / Macro Analysis

- अधिक से अधिक प्रश्नों के उत्तर लिखें।
- प्रश्न के सभी आयामों को पूरा करने की कोशिश करें।
- तथ्यों की प्रस्तुति पर ध्यान दें।

Grade Card	
Grade 'A'	Very Good
Grade 'B'	Good
Grade 'C'	Satisfactory
Grade 'D'	Poor

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान पर प्रश्न संख्या के अलावा कुछ न लिखें। (Please do not write anything except the question number in this space)

1. "प्रतिस्पर्द्धात्मक संघवाद यद्यपि निवेश और प्रतिभा को आकर्षित करने के संबंध में परिवर्तन का शक्तिशाली एजेंट होता है, परंतु अनिवार्य सेवाओं की डिलीवरी के संबंध में यह अपेक्षाकृत कमज़ोर रहा है।" भारतीय राज्यों के संदर्भ में उक्त कथन का व्याख्या कीजिये। (250 शब्द) 12.5

"Although the competitive federalism is a powerful agent of change in relation to attracting investment and talent but with regard to the delivery of essential services it has been comparatively weak." Explain the statement given above with reference to the Indian states. (250 words) 12.5

प्रतिस्पर्द्धात्मक संघवाद, संघवाद का एक ऐसा मॉडल है जिसमें केन्द्र व राज्य तथा राज्य व राज्य (मुख्यतः) आपस में प्रतिस्पर्द्धा करते हैं ताकि सामाजिक-आर्थिक विकास को सुनिश्चित कर सके।

प्रतिस्पर्द्धी संघवाद में राज्यों के द्वारा निवेश व प्रतिभाओं को आकर्षित करने का विशेष प्रयास होता है क्योंकि निवेश आने से राज्य का औद्योगीकरण होगा, इससे रोजगार के साधन उत्पन्न होंगे, लोगों की आय बढ़ेगी, गरीबी का ह्रास होगा।

अतः निवेश व प्रतिभाओं को आकर्षित करने के लिए राज्यों द्वारा कई कदम उठाये जा रहे हैं —

① निवेशक सम्मेलन का आयोजन → 'वाइब्रेंट गुजरात' की तर्ज पर हर राज्य निवेशक सम्मेलन का आयोजन कर रहा है।

② भूमि अधिग्रहण व्यवस्था में सुधार → इसके लिए राज्यों ने अपने स्तर पर प्रयास किये (जैसे आन्ध्र प्रदेश में लैंड लीज की अवधि 33 साल से बढ़ाकर 99 साल कर दी। इसी तरह

कृपया इस स्थान पर कुछ न लिखें। (Please don't write anything in this space)

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या अंकित करें न लिखें। (Please do not write anything except the question number in this space)

गुजरात ने सामाजिक अवसंरचना के लिए भूमि इंफ्रास्ट्रक्चर पर्यावरण प्रभाव अध्ययन (EIA) को खत्म कर दिया है।

श्रम कानूनों में सुधार — गुजरात ने 'औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947' में संशोधन करके 100 श्रमिकों की सीमा को बढ़ाकर 300 श्रमिक कर दिया है ऐसे ही सुधार महाराष्ट्र ने भी किये हैं।

हाल ही देखते हैं कि निवेश व प्रतिभाओं को आकर्षित करने में राज्यों की प्रतिस्पर्धा रही है परंतु अनिवार्य सेवाओं की डिलीवरी में यह प्रतिस्पर्धा कमजोर रही है- जैसे- मिड डे मिल की सुरुआत तमिलनाडु में हुई तथा यह पूरे देश में अनुकरित की गयी परंतु मिड डे मिल में जैसी सफलता दक्षिणी राज्यों में देखने को मिली वह उत्तर भारत के राज्यों में नहीं मिली। इसने दक्षिण भारत में शिक्षा में नामांकन दर बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। इसी तरह अगर खाद्य सुरक्षा के लिए चलायी जा रही PDS स्कीम पर ध्यान दें तो दानदी में अर्जित शांता कुमार कमिटि ने रेखांकित किया है कि PDS में औसतन लीकेज 48% है तथा यह राज्यों के बीच 20% से लेकर 70% के बीच पाया जाता है।

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या अंकित करें न लिखें। (Please do not write anything except the question number in this space)

दक्षिणी राज्यों ने PDS व्यवस्था का बेहतर क्रियान्वयन किया है वहीं उत्तर भारतीय राज्य इसमें पिछड़े रहे हैं जबकि देश की कुल गरीब जनसंख्या का लगभग 71% इन्हीं उत्तर भारतीय राज्यों में आता है।

अतः आवश्यक है कि बुनियादी सेवाओं की डिलिवरी में भी राज्य आपस में प्रतिस्पर्धा करें। एक दूसरे के Best Practices का अध्ययन कर उसका अपने यहाँ अनुकरण करें। आर्थिक समीक्षा ने प्रतिस्पर्धी संघवाद को प्रतिस्पर्धी उप संघवाद (Competitive Sub-Federalism) की ओर उन्मुख करने पर बल दिया है जिसमें राज्यों के स्तर से नीचे जाकर शहरी स्थानीय संस्थाओं (ULBs), जिले (Districts) आदि के बीच भी आपस में प्रतिस्पर्धा हो। साथ ही इन संस्थाओं द्वारा दी जा रही सेवाओं के सम्बन्ध में पब्लिक रेटिंग पर भी बल दिया गया है।

4-5

	Introduction	Context	Content	Language	Current Link / Examples	Conclusion	Error
Marks	0.25	2	2.5	0.25		0.5	
Grade	B	B	C	C		A	

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

2. "परिचालन में नकदी का अनुपात बढ़ने से भ्रष्टाचार के मामलों में भी इजाफा होता है।" पारदर्शिता अंतर्राष्ट्रीय (Transparency International) द्वारा किये गए इस आकलन की भारतीय अर्थव्यवस्था में हुए हालिया विमुद्रीकरण के संदर्भ में पुष्टि कीजिये। (250 शब्द) 12.5

"Increased ratio of cash in circulation also increases corruption related cases." Substantiate this assessment conducted by transparency international in the context of recent demonetization in the Indian economy. (250 words) 12.5

भारत में Cash to GDP अनुपात औसतन 12% के आस पास रहा है जबकि OECD के देशों में यह आंकड़ा 4% के आस पास है। यह अर्थव्यवस्था में नकदी का प्रचलन अधिक होने से अवैध गतिविधियों जैसे सरकार से टैक्स चुराना, भ्रष्टाचार आदि का प्रभाव अधिक होता है। इसी संदर्भ में Cashless economy (नकदरहित अर्थव्यवस्था) के निर्माण पर बल दिया जाता है।

इसी संदर्भ में दिनांक 8 नवंबर 2016 में सरकार ने 500 व 1000 रु के बड़े नोटों के विमुद्रीकरण का फैसला लिया। ताकि भ्रष्टाचार पर नियंत्रण हो, काले धन पर नियंत्रण हो, नकली मुद्रा प्रचलन से बाहर हो, व आतंकी वित्त पोषण में कमी आये। परन्तु इन प्रत्यक्ष उद्देश्यों के अलावा कई और अप्रत्यक्ष उद्देश्य भी थे जिसमें प्रमुख नकदरहित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना था।

विमुद्रीकरण के कारण लोगों के पास तत्काल नकदी उपलब्ध न होने के कारण बैंकों के माध्यम से डिजिटलीकरण, क्रेडिट व डेबिट कार्ड, मोबाइल वॉलेट, ई-वॉलेट,

दृष्टि The Vision
641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष : 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356
ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com
फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation, ट्विटर: twitter.com/drishtiias
Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

आदि का प्रचलन तेजी से बढ़ा।

परन्तु विमुद्रीकरण के बाद के अध्ययनों में पाया गया है कि जनवरी – मार्च 2017 के बीच डिजिटलेशन ट्रांजैक्शन में लगभग 149% की बढ़ोतरी हुई जो जून 2017 तक आते आते गिरकर 128% हो गयी। जो यह दिखाती है कि अल्पकालीन समय के लिए डिजिटलीकरण को बढ़ावा मिला परन्तु यह दीर्घकालिक प्रभाव नहीं उभर पाया।

परन्तु विमुद्रीकरण के बाद सरकार ने कैशलेस अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए और कई उपाय किये जैसे – यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) आधारित BHIM एप, IRCTC से ऑनलाइन टिकट बुक करने पर सेवा कर से मुक्ति आदि। अतः प्रयास निरंतर जारी है।

RBI के Vision Document 2018 में भी नकदीरहित अर्थव्यवस्था की ओर आगे बढ़ने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए वैकिंग अवसंरचना का तेजी से प्रसार, वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने आदि पर बल दिया गया है। सरकार भी DBT (Direct Benefit Transfer) के द्वारा JAM आधार का उपयोग कर सब्सिडी को सीधे लाभार्थियों तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है।

दृष्टि The Vision
641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष : 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356
ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com
फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation, ट्विटर: twitter.com/drishtiias
Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

	Introduction	Context	Content	Language	Current Link / Examples	Conclusion	Error
Marks	0.25	0.5	1.5	0.25			
Grade	B	D	C	C			

दृष्टि The Vision
641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष : 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356
ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com
फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation, ट्विटर: twitter.com/drishtiias
Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

3. "न्यायसंगत समाज में प्रत्येक व्यक्ति को न्यूनतम आय की गारंटी देने की आवश्यकता है।" कथन की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिये। (250 शब्द) 12.5

"In a justified society there is a need to guarantee minimum income to each person." Critically explain the statement. (250 words) 12.5

कवि नागार्जुन के कविता की कुछ पंक्तियां है- 'जहाँ न भरता पेट, देश वह कैसा भी है, मशानरुक है' टामस पेन से लेकर जॉन ब्रॉल्स तक सभी ने माना है कि ऐसा राज्य जो अपने नागरिकों की न्यूनतम आय सुनिश्चित कर पाने में असफल है, न्यायसंगत राज्य नहीं कहा जा सकता। गांधी जी भी मानते थे- 'Poverty is the worst kind of violence'.

इसी मद्देनजर को ध्यान में रखते हुये लोगों को न्यूनतम आय उपलब्ध कराने हेतु यूनिवर्सल बेसिक इनकम (UBI) पर बल दिया जाता है। आर्थिक समीक्षा ने भी इस पर पर्याप्त विचार विमर्श करने की बात कही है। यह कहा गया है कि सार्वभौमिक (universal) रूप से व बिना किसी शर्त के (unconditional) नागरिकों को न्यूनतम आय उपलब्ध कराई जानी चाहिए। ऐसा करने से

① सभी नागरिकों की आय का स्तर ऐसा स्तर होगा जिसमें कोई भी व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे न जा सकेगा।

② इससे उनमें स्वायत्तता (autonomy) होगी व अपनी जरूरत के अनुसार सेवाओं का उपभोग कर सकेंगे।

③ UBI के सेवाओं की डिलीवरी में होने वाले लीकेज, भ्रष्टाचार पर भी लगाम लगायी जा सकेगी व वास्तविक

दृष्टि The Vision
641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष : 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356
ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com
फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation, ट्विटर: twitter.com/drishtiias
Copyright – Drishti The Vision Foundation

दृष्टि The Vision

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

लाभार्थी तक लाभ पहुँच सकेगा।

5) ग्राम ही जनता का आय का स्तर बढ़ने से उनके उपभोग का भी स्तर बढ़ेगा तथा इससे अर्थव्यवस्था में भी गति आयेगी।

न्यूनतम पहुँच सुनिश्चित करने के पीछे अन्नपायी क्षम के सिद्धान्त (Diminishing Principle) को माना है कि बिना श्रम के किसी व्यक्ति को भी भोजन नहीं दिया जाना चाहिए। वे कहते हैं - 'कोई भी व्यक्ति जो ऐसी रोटी खा रहा है, जिसके लिये उसने कोई श्रम नहीं किया है चोरी की रोटी खा रहा है।

निष्कर्ष रूप से न्यूनतम आय की गारंटी देने में कई समस्यायें भी है -

① यह लोगों में अकर्मण्यता को बढ़ायेगी।

② नीचे पैसा आने पर इसका दुरुपयोग ज्यादा होगा। चूँकि हमारा समाज अभी भी पुरुष प्रधान ही है अतः यह संभावना है कि पैसे का दुरुपयोग शराब व अन्य व्यसनों में बढ़ेगा तथा महिलाओं व बच्चों की आवश्यकताओं की अवहेलना होगी।

③ इससे राज्य के राजस्व पर भी अत्यधिक बोझ बढ़ेगा। लगभग 5-6% GDP का, इस पर खर्च करना होगा जो राजकोषीय घाटे को बढ़ायेगा।

Copyright – Drishti The Vision Foundation

दृष्टि The Vision

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर कहा जा सकता है कि न्यूनतम आय उपलब्ध कराने की दिशा में अभी पर्याप्त विमर्श-विवेचन की आवश्यकता है। साथ ही जबतक UBI की व्यवस्था न हो सकारा यह ध्यान रखे कि सेवाओं की डिलीवरी में लीकेज न हो, जिससे लाभार्थी तक सेवायें पहुँच सके। तभी हम एक गरीबी मुक्त, भूखमरी मुक्त, बेरोजगारी मुक्त 'New India' का निर्माण कर सकते हैं।

3

	Introduction	Context	Content	Language	Current Link / Examples	Conclusion	Error
Marks	0.25	1	1.25	0.25		0.25	
Grade							

Copyright – Drishti The Vision Foundation

दृष्टि The Vision

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें। (Please do not write anything except the question number in this space)

4. निर्यात की मात्रा विभिन्न आंतरिक एवं अंतर्राष्ट्रीय कारकों से प्रभावित होती है। इस संदर्भ में भारत सरकार द्वारा 'निर्यात संवर्द्धन' के लिये उठाए गए विभिन्न कदमों की विवेचना कीजिये। (250 शब्द) 12.5

Export volume is affected by various internal and international factors. In this context discuss the various steps taken by the government of India for 'Export Promotion'. (250 words) 12.5

कहा जाता है कि यदि भारतीय अर्थव्यवस्था को 8-10% का आर्थिक वृद्धि पर को प्राप्त करना है तो उसे निर्यात को 20-25% तेज करना होगा। (IMF की World Economic outlook रिपोर्ट 2017)

उ: भारत ने आर्थिक उदारीकरण के बाद से निर्यात को बढ़ाने पर विशेष बल दिया है। इस संदर्भ में सरकार ने 'Focused Market Scheme' व 'Focus Product Scheme' की शुरुआत की जिसका उद्देश्य नये बाजारों व नये उत्पादों की खोज करनी थी जिसका निर्यात बढ़ाने में योगदान हो।

~~इसके~~ लेकिन एक देश की निर्यात कई आंतरिक व बाह्य कारकों से प्रभावित होती है जैसे— देश में विनिर्माण क्षेत्र की स्थिति कैसी है, सरकार की निर्यात प्रोत्साहन की नीति क्या है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में माँग कैसा है, विशेषतः भारत में श्रम कानूनों का जटिल होना, भूमि अधिग्रहण में कठिनाई, अवसंरचना की कमजोर स्थिति, कौशल युक्त श्रम बल का अभाव आदि व्यापार सुनिश्चित करने में बड़े बाधक रहे हैं। इसी तरह 2008 की वैश्विक आर्थिक मंदी के बाद से विकसित देशों में बाजार के धीमा रहने से भी निर्यात पर नकारात्मक असर पड़ा। इसके बाद यूरोजोन संकट ने इसे और गंभीर किया। हाल के समय में संरक्षणवादी नीतियों का बढ़ता प्रभाव एक बड़ी समस्या है। इसे BREXIT, H1B visa को कठिन करना आदि के रूप में देखा जा सकता है। उ: वैश्वीकरण को कई चुनौती मिलने लगी है जो पुनः निर्यात की संभावनाओं को घटाता है।

उ: उपरोक्त समस्याओं से निपटने के लिए सरकार ने विदेश व्यापार नीति 2015-20 की घोषणा की जिसमें विदेशी व्यापार (निर्यात) के स्तर को $466 बिलियन से बढ़ाकर $900 बिलियन करने का लक्ष्य रखा गया है साथ ही वैश्विक निर्यात में भारतीय हिस्सेदारी को 2% से बढ़ाकर 3% करने का लक्ष्य रखा गया है इसमें मुख्यतः दो स्कीमें MEIS (Merchandise export from India scheme) व SEIS (service Export from India scheme) को शामिल किया गया है। तथा Duty credit script का भी

641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष : 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356
ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com
फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation, ट्विटर: twitter.com/drishtiias
Copyright – Drishti The Vision Foundation

दृष्टि The Vision

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें। (Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें। (Please don't write anything in this space)

13
641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष : 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356
ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com
फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation, ट्विटर: twitter.com/drishtiias
Copyright – Drishti The Vision Foundation

दृष्टि The Vision

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें। (Please do not write anything except the question number in this space)

विचार किया गया है। इसके अलावा SEZ को भी Duty credit Receipt की संकल्पना में शामिल कर लिया गया है।

इसके साथ ही घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए DCR (Domestic Content Requirement) व मूल्य संवर्धन (Value Addition) वाले उत्पाद को प्रोत्साहित करने [illegible] भी बनायी गयी है। साथ ही राज्यों को भी अपनी व्यापार नीति को नयी नीति के सामंजस्य बनाने पर बल दिया गया है।

इसके अलावा हम नये मार्केट की खोज के लिए मुक्त व्यापार समझौते (FTA) पर भी बल दे रहे हैं जिसमें मुख्य 'भारत-EU FTA' व 'RCEP' है।

इसके साथ ही घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए FDI को उदारीकृत (कई क्षेत्रों में) किया गया है; जैसे रक्षा क्षेत्र, सिंगल ब्रांड, मल्टी ब्रांड आदि पर भी बल दिया गया है।

	Introduction	Context	Content	Language	Current Link / Examples	Conclusion	Error
Marks	0.25	1.5	2	1.25			
Grade	B	C	B	C			

दृष्टि The Vision
641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष : 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356
ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com
फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation, ट्विटर: twitter.com/drishtiias
Copyright – Drishti The Vision Foundation

दृष्टि The Vision

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें। (Please do not write anything except the question number in this space)

5. "यद्यपि भारतीय उद्योग तेजी से बढ़ रहे हैं परंतु आधारभूत उद्योगों में से एक उर्वरक उद्योग अपनी घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति में भी निरंतर असफल रहा है।" कथन के संदर्भ में भारतीय उर्वरक उद्योग के समक्ष उपस्थित चुनौतियों का विवरण दें तथा इनसे निपटने के उपायों पर चर्चा कीजिये। (250 शब्द) 12.5

"Although Indian industry is growing steadily but the fertilizer industry being one of the basic industries, has been consistently unable to fulfill its domestic needs." In the context of the statement, describe the challenges before the Indian fertilizer industry and discuss the measures to deal with them. (250 words) 12.5

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें। (Please don't write anything in this space)

हरित क्रांति का लाभ उठाने के लिए उर्वरक उद्योग को देश में तेजी से प्रोत्साहित किया गया। हालाँकि इसका लाभ भी देखने को मिला परन्तु सरकार की नीतियों के कारण यह उद्योग पिछड़ा बना रहा। सरकार ने 2003 से पहले RPS (Retention Price Scheme) अपनायी जिसमें उर्वरक उत्पादक कंपनियों को एक निश्चित लाभ देते हुये सब्सिडी सुनिश्चित की गयी। परन्तु यह नीति प्रभावशाली नहीं रही और तब सरकार ने NPS (New Pricing Scheme) शुरू की परन्तु आज भी उर्वरक उद्योग की हालत खस्ता है। उर्वरक उद्योग के समक्ष कई समस्यायें हैं—

(1) भारत में केवल यूरिया व कुछ मात्रा में फॉस्फोरस उर्वरक का उत्पादन होता है तथा पोटाश उर्वरक का भारत पूरी तरह आयात करता है। चूँकि उर्वरक का निर्माण प्राकृतिक गैस से ही होता है अतः यूरिया व फॉस्फोरस के उत्पादन में भी प्राकृतिक गैस के आयात पर निर्भर होते हैं जो हमारे आयात बिल को बढ़ाता है।

(2) पहले कुछ समय में यूरिया का आयात भी

दृष्टि The Vision
641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष : 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356
ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com
फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation, ट्विटर: twitter.com/drishtiias
Copyright – Drishti The Vision Foundation

करना पड़ेगा जो सरकार के भारीभरी सब्सिडी को देखते हुए बढ़ाना है। (लगभग 69000 करोड़ की सालाना) उर्वरक क्षेत्र को दी जाने वाली सब्सिडी

(3) उर्वरक उद्योग के लाभ की मात्रा सुनिश्चित कर देने से इस क्षेत्र में उत्पादन क्षमता का विस्तार बहुत कम हुआ है।

(4) मौजूदा उर्वरकों के अवैध रूप से अन्य उद्योगों की तरफ diversion भी हुआ है जैसे केमिकल उद्योग में, मिलावटी दूध के निर्माण में। इसके अलावा अन्य देशों से भी अवैध रूप से स्मगल किया जाता है।

अतः उपरोक्त समस्याओं को ध्यान में रखते हुए यह सुझाव दी जाती है कि (1) यूरिया को decontrol किया जाये (योजना आयोग द्वारा गठित सौमित्र चौधरी समिति की सिफारिश)

(2) इसके अलावा Nutrient Based subsidy (NBS) को इसी फॉस्फोरस व पोटाश उर्वरकों में लागू की उसके तहत यूरिया को भी लाया किया जाये।

(3) सरकार ने New urea Policy 2015 की भी घोषणा की जिसके यूरिया के उत्पादन में 2 मिलियन टन की वृद्धि का लक्ष्य रखा है साथ ही उर्वरक प्लांटों की ऊर्जा दक्षता (energy efficiency) को भी बढ़ाने का लक्ष्य है।

दृष्टि The Vision
641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष : 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356
ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com
फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation, ट्विटर: twitter.com/drishtiias
Copyright – Drishti The Vision Foundation

(4) इसके अलावा 'Neem coated urea' को भी अनिवार्य बनाया गया है। उर्वरक कंपनियों को - प्रतिशत यूरिया को अनिवार्य रूप से नीम कोटिंग करनी होगी। पर नीमकोटिंग 100% तक अनुमति नहीं है इसका उद्देश्य यूरिया के diversion को रोकना है।

अतः इसके उद्योग के उद्योग में यूरिया की खपत के लिए प्रयास करें।

	Introduction	Context	Content	Language	Current Link / Examples	Conclusion	Error
Marks	0.25	1	1	0.25	0.25	0.25	
Grade							

दृष्टि The Vision
641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष : 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356
ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com
फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation, ट्विटर: twitter.com/drishtiias
Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

6. खाद्य सुरक्षा से आगे बढ़कर पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने की राह में दलहन समस्या मुख्य बाधा है। इस बाधा पर चर्चा कीजिये और बताएँ कि इसे कैसे दूर किया जा सकता है? (250 शब्द)
12.5

Pulses Problem is the main obstacle in the path of ensuring nutritional security ahead of food security. Discuss this obstacle and tell how it can be overcome. (250 words)
12.5

भारत में अभी तक खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने पर बल दिया जाता है जबकि जरूरत है कि खाद्य सुरक्षा के साथ पोषण सुरक्षा को भी सुनिश्चित किया जाये। क्योंकि पर्याप्त पोषण के अभाव में भारतीय कई रूपों में कुपोषण के शिकार रहे हैं।

पोषण सुरक्षा को सुनिश्चित करने की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण कदम दालों की उपलब्धता को बढ़ाया जाता है दाल को 'गरीबों का प्रोटीन' की भी संज्ञा दी जाती है परन्तु भारत में प्रति व्यक्ति दाल की उपलब्धता बहुत कम है। हालांकि यह विडम्बना है कि भारत विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है, सबसे बड़ा आयातक है, व सबसे बड़ा उपभोक्ता है फिर भी हम सभी नागरिकों को दाल की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं कर पा रहे हैं।

भारत में लगभग 18 मिलियन टन (MT) दालों का उत्पादन होता है जबकि आवश्यकता लगभग 23 MT की है अतः हमें 4-5 मिलियन टन दाल बाहर से आयात करने पड़ते हैं यह कुल जरूरत का लगभग 20% है। इसी तरह आर्थिक समीक्षा में भी कहा

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

गया है कि भारत में कृषि उत्पादन cereal centric है अर्थात् धान की MSP की नीति भी अनाजों के उत्पादन को दालों से अधिक लाभदायक बनाती है न कि दालों में। चूंकि दाल शुष्क भूमि पर भी उगा सकते हैं अतः पाया गया है कि भारत में अच्छी उपजाऊ भूमि पर तो अनाजों को और शुष्क भूमि पर दालों को उगाया जाता है जिससे दालों की प्रति हेक्टेयर उत्पादकता बहुत कम होती है। इसके अलावा दालों के उत्पादन को बढ़ाने के लिये पर्याप्त अनुसंधान व विकास (R&D) पर भी ध्यान नहीं दिया गया है।

अतः सरकार ने उपरोक्त समस्याओं पर ध्यान केन्द्रित करते हुये निम्न उपायों द्वारा दालों की उपलब्धता सुनिश्चित करने का प्रयास किया है—

(1) MSP तथा खरीद में वृद्धि: धान और गेहूँ की तुलना में दालों को MSP में खासकर जिन्हें लगभग 90% किसान की हड़ी उगाते हैं दालों में पर्याप्त वृद्धि की गई है।

(2) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (NFSM) 2008 में भी दालों के उत्पादन में 2 मिलियन टन की बढ़ोत्तरी का लक्ष्य रखा है।

इसी तरह ISOPOM (Integrated Scheme for Oilseeds, Palm & Pulses) के तहत भी दालों पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया गया है।

Copyright – Drishti The Vision Foundation

(5) इसके अलावा अरविन्द सुब्रह्मण्यम समिति की अनुशंसाओं को भी लागू करने का प्रयास किया जा रहा है जिसमें NAFED व SFAC (Small Farmer Agricultural Consortium) द्वारा दालों की सरकारी खरीद बढ़ाने पर बल दिया गया है।

(6) सरकार ने मूल्यों में उतार चढ़ाव पर नियंत्रण के लिए 'Price stabilization fund' (मूल्य स्थिरीकरण कोष) भी बनाया है।

	Introduction	Context	Content	Language	Current Link / Examples	Conclusion	Error
Marks	0.25	1	1	0.25			
Grade							

दृष्टि The Vision
641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष : 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356
ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com
फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation, ट्विटर: twitter.com/drishtiias
Copyright – Drishti The Vision Foundation

7. "प्रथम विश्व युद्धोत्तरकालीन अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की दुर्बलताएँ ही द्वितीय विश्व युद्ध का मूल कारण सिद्ध हुईं।" आलोचनात्मक परीक्षण कीजिये। (250 शब्द) 12.5

"The weaknesses of the international order in the time of post World War I were proved the root cause of World War II." Critically examine. (250 words) 12.5

कहा जाता है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद की अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था ही द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बनी। इसे निम्न रूप में देखा जा सकता है –

(1) पेरिस शांति सम्मेलन में जर्मनी की अपमानजनक संधि, इटली व जापान को मित्र राष्ट्रों द्वारा उचित लाभ का हिस्सा न दिया जाना भी बड़ी समस्या बना। जर्मनी की संधि ने जर्मनी के वाइमर गणराज्य को कमजोर किया जिसने जर्मनी में नाजीवादी दल को मजबूत किया। इसी तरह इटली में भी संकट जनता की भावनाओं का लाभ उठाकर मुसोलिनी का फासीवादी दल मजबूत बना।

(2) आर्थिक संकट – प्रथम विश्व युद्ध के बाद आर्थिक स्थितियाँ सभी देशों की कमजोर हुई अर्थात् यूरोपीय देश अमेरिका से ज्यादा ऋण को वापस लौटाने में असक्षम होने लगे जिससे न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज धराशायी हो गयी जिसने 1929 की वैश्विक आर्थिक मंदी को जन्म दिया। इसी तरह भारी जुर्माने (6600 बिलियन पौंड) के कारण जर्मनी की अर्थव्यवस्था पहले से ही गर्त में

दृष्टि The Vision
641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष : 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356
ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com
फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation, ट्विटर: twitter.com/drishtiias
Copyright – Drishti The Vision Foundation

थी अतः वैश्विक संकट ने आर्थिक चुनौतियों को और गंभीर किया जिसने नाजीवादी व फासीवादी दलों को आगे बढ़ने के अवसर दिये।

(3) राष्ट्रसंघ का कमजोर होना — 'अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में नैतिकता पर आधारित शक्ति एक अपूर्ण शक्ति मानी जाती है।" राष्ट्रसंघ का गठन तो हुआ परंतु अमेरिका, रूस जैसे देश संघ के सदस्य नहीं थे इसी तरह संघ का संविधागत आधार भी कमजोर था- न कोई पुलिस, न कोई सैनिक अतः अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था को बनाये रखने में असफल रहा।

(4) परंतु केवल प्रथम विश्व युद्ध के बाद ही व्यवस्था को ही जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। ब्रिटेन व फ्रांस की तुष्टिकरण की नीति भी उतनी ही जिम्मेदार थी। ब्रिटेन का जर्मनी के नौसैनिक सम्मेलन करना, जर्मनी का निरस्त्रीकरण सम्मेलन से बाहर आना, जर्मनी, जापान व इटली का राष्ट्रसंघ से बाहर आना, जर्मनी का वर्साय की संधि की शर्तों को मानने से इनकार कर देना इसी तुष्टिकरण

दृष्टि The Vision
641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष : 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356
ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com
फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation, ट्विटर: twitter.com/drishtiias
Copyright – Drishti The Vision Foundation

की नीति के तहत ही फल-फूल रहे थे।
इसके अलावा जर्मनी द्वारा पहले चेकोस्लोवाकिया के सुडेटनलैण्ड छीन लेना, फिर चेकोस्लोवाकिया और भी अधिकार क्षेत्र लेना इसी तरह इटली व जापान की साम्राज्यवादी प्रवृत्ति को भी रोकने में [illegible] असफल रहे। इन सभी ने मिलकर द्वितीय विश्व युद्ध की नींव रखी।

3

	Introduction	Context	Content	Language	Current Link / Examples	Conclusion	Error
Marks	0.5	1	1	0.25	[illegible]	[illegible]	
Grade	B	D1	D1	[illegible]	[illegible]	A	

दृष्टि The Vision
641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष : 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356
ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com
फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation, ट्विटर: twitter.com/drishtiias
Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें। (Please do not write anything except the question number in this space)

8. "फ्रांस की क्रांति वैचारिक एवं आर्थिक रूप से सशक्त होते समाज के असंतोष की अभिव्यक्ति मात्र थी।" विश्लेषण कीजिये। (250 शब्द) 12.5

"The french revolution was an expression of discontent of the ideologically and financially empowering society." Analyse. (250 words) 12.5

फ्रांस की क्रांति का मुख्य कारण ही सामाजिक विभाजन था। समाज में तीन वर्ग थे जिनमें विशेषाधिकारों का बंटवारा काफी असमान था। जिस कारण मध्य वर्ग व निम्न वर्ग में असंतोष था।

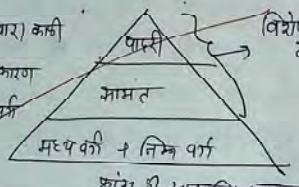

अतः मध्य वर्ग जो वैचारिक रूप से मजबूत था, यहाँ तक आर्थिक रूप से भी अच्छी स्थिति में था परंतु उसके दो वर्गों के कारण कोई राजनीतिक अधिकार प्राप्त करने की स्थिति में नहीं था अतः मध्य वर्ग में रोष था। इसी मध्यवर्ग जो निम्न वर्ग की स्थिति को और भड़काकर क्रांति की नींव रखी।

परंतु क्या केवल समाज के असंतोष को इसी रूप में नहीं माना जा सकता। इसके अलावा भी राजनीतिक रूप में अक्षम राजतंत्र भी विद्यमान था। पुराने वर्ग का शासक लुई चौदहवें के शासनकाल में कोई रुचि नहीं थी। इसी भारी आंतरिक का शासन में अत्यधिक हस्तक्षेप था अर्थात् प्रशासनिक व्यवस्था

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें। (Please do not write anything except the question number in this space)

में व्याप्त भ्रष्टाचार व कुकुशलता से भी जनता आक्रोशित थी।

परंतु केवल समाज का असंतोष ही क्रांति के लिए उत्तरदायी नहीं कहा जा सकता। इसके ऐतिहासिक निहितार्थ भी थे। यूरोप में इंग्लैंड व फ्रांस का लगातार युद्धों में उलझे रहना (सप्तवर्षीय युद्ध 1756-63) ने भी फ्रांस की अर्थव्यवस्था को कमजोर किया। साथ ही फ्रांस में हुए औद्योगीकरण की धीमी रफ्तार व विभिन्न कारण जैसे कि तकनीकी के पिछड़े आयात ने भी अर्थव्यवस्था व उद्योगों की हालत को खस्ता कर दिया। इसके साथ ही कृषि में प्राकृतिक आपदा ने लोगों को रोटी के लिए दंगे करने को प्रोत्साहित कर दिया।

इसके साथ ही फ्रांस की क्रांति को सफल बनाने में विचारकों की भी भूमिका अहम थी। रूसो ने 'Social contract' में राज्य में जनता की संप्रभुता को सर्वोच्च बताया तो इसी मांटेस्क्यू ने 'शक्ति के पृथक्करण' के द्वारा कार्यपालिका, विधायिका व न्यायपालिका की शक्तियों को पृथक् करने पर बल दिया। तो वाल्तेयर ने मानवाधिकारों पर बल देते हुये मानव की स्वतंत्रता

Copyright – Drishti The Vision Foundation

दृष्टि The Vision

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

श्री अवधारणा, उसके वाद अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने पर बल दिया।

स्थिति के विश्लेषण: क्या यह कहना है कि क्रांति की सफलता का केवल सामाजिक आधार ही नहीं था बल्कि राजनीतिक, आर्थिक व वैचारिक स्थितियों ने भी उत्तरदायी योगदान किया।

आर्थिक सफलता

3

	Introduction	Context	Content	Language	Current Link / Examples	Conclusion	Error
Marks	0.25	1	1	0.25		0.5	
Grade	B	D+	D+	BC		A	

दृष्टि The Vision
641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष : 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356
ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com
फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation, ट्विटर: twitter.com/drishtiias

Copyright – Drishti The Vision Foundation

दृष्टि The Vision

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

9. जैसे सूर्य की किरणें समस्त संसार में विकसित होती हैं, चाहे आगे या पीछे, वैसे ही ज्ञान का प्रकाश किसी एक महाद्वीप तक कैसे सीमित रह सकता है? पुनर्जागरण के दौरान उपजे विचार के संदर्भ में उक्त कथन की विवेचना कीजिये। (250 शब्द) 12.5

As the rays of the sun spread throughout the world, whether early or later similarly, how the light of intelligence can be confined to one continent? Discuss the above statement in relation to the idea that was developed during the Renaissance. (250 words) 12.5

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

दृष्टि The Vision
641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष : 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356
ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com
फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation, ट्विटर: twitter.com/drishtiias

Copyright – Drishti The Vision Foundation

प्रश्न-पत्र के लिये विशिष्ट अनुदेश

कृपया प्रश्नों का उत्तर देने से पूर्व निम्नलिखित प्रत्येक अनुदेश को ध्यानपूर्वक पढ़ें:

इसमें **बीस** प्रश्न हैं तथा हिन्दी और अंग्रेज़ी दोनों में छपे हैं।

सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।

प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सामने दिये गए हैं।

प्रश्नों के उत्तर उसी माध्यम में लिखे जाने चाहियें जिसका उल्लेख आपके प्रवेश-पत्र में किया गया है, और इस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न-सह-उत्तर (क्यू.सी.ए.) पुस्तिका के मुख-पृष्ठ पर अंकित निर्दिष्ट स्थान पर किया जाना चाहिये। उल्लिखित माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में लिखे गए उत्तर पर कोई अंक नहीं मिलेंगे।

प्रश्नों में शब्द सीमा, जहाँ विनिर्दिष्ट है, का अनुसरण किया जाना चाहिये।

प्रश्न-सह-उत्तर-पुस्तिका में खाली छोड़ा हुआ पृष्ठ या उसके अंश को स्पष्ट रूप से काटा जाना चाहिये।

QUESTION PAPER SPECIFIC INSTRUCTIONS

Please read each of the following instruction carefully before attempting questions:

*There are **TWENTY** questions printed both in **HINDI** and in **ENGLISH**.*

All the questions are compulsory.

The number of marks carried by a question is indicated against it.

Answers must be written in the medium authorized in the Admission Certificate which must be stated clearly on the cover of this Question-cum-Answer (QCA) Booklet in the space provided. No marks will be given for answers written in a medium other than the authorized one.

Word limit in questions, wherever specified, should be adhered to.

Any page or portion of the page left blank in the Question-cum-Answer Booklet must be clearly struck off.

रफ कार्य के लिये स्थान

(Space for Rough Work)

Copyright – Drishti The Vision Foundation